

# जनता को जिम्मेदार सरकार चुननी है, चौकीदार नहीं!

नवीन जोशी

हमारे देश में चुनावों के दौरान जनता को सबसे ज्यादा ठगा, भरमाया और ललचाया जाता है, जबकि होना उलटा चाहिए था। यह समय जनता द्वारा नेताओं के कान पकड़ने, उन्हें उनके अधूरे या भूले वादों की याद दिलाने, ज्वलंत और रोजमर्रा मुद्दों को उठाने और भविष्य की योजनाओं एवं दृष्टि के बारे में पूछने का होना चाहिए था।

नेता चुनाव के समय ही जनता के पास जाते हैं। इसलिए यह समय उन्हें ठीक से अपनी बात सुनाने का, उनकी असलियत पहचानने का और उन्हें उत्तरदाई ठहराने का होना चाहिए।

अफसोस कि ऐसा नहीं होता। उल्टे, नेता जनता को ही असली मुद्दों से दूर ले जाने और अपने अनकिये-किये पर पर्दा डालने का काम बखूबी कर जाते हैं।

अब यही देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने 'मैं भी चौकीदार' अभियान चला दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने अपना नाम 'चौकीदार नरेंद्र मोदी' रख लिया है। उनकी देखा-देखी भाजपा के लगभग सारे केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया खाते में नाम से पहले 'चौकीदार' लगा लिया है। सबमें 'चौकीदार' बनने की होड़ लगी है।

क्यों, चौकीदार क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' चला दिया। जुमले गढ़ने में माहिर मोदी जी ने किसी सभा में कहा था कि - 'मैं देश के धन का चौकीदार हूँ'। राफेल सौदे में हुई अनियमितताओं को मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने नारा गड़ लिया था- 'चौकीदार चोर है'। यह मामला जोर पकड़ने लगा तो मोदी जी की टीम 'चौकीदार' की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थापित करने में लग गयी। सो, बकायदा अभियान चलाकर प्रधानमंत्री समेत सब भाजपाई 'चौकीदार' बन गये हैं।

अब सारी बहस 'चौकीदार' के इर्द-गिर्द घूम रही है। राहुल 'चौकीदार चोर है' नारे के साथ मैदान में डटे हैं तो प्रियंका का तर्क है कि 'चौकीदार तो अमीरों के होते हैं।' यानी विपक्षी नेता भी 'चौकीदार' के खेल में उलझा दिये गये हैं। क्या खूब खेल है और कैसे चतुर खिलाड़ी!

2019 के आम चुनाव में हमें 'चौकीदार' चुनना है या ऐसी सरकार जो देश को संविधान की भावना के अनुरूप चलाते हुए जनता की भलाई के लिए काम कर सके?

2014 में हमने 'चाय वाला' चुना था क्या? राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, चाय बेचने वाले आदमी के रूप में नहीं।

याद ही होगा कि 2014 के चुनाव में



यह वक्त है कि जनता पूछे और वे बताएँ कि पाँच साल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने वादों पर कितना अमल किया? वे बताएँ कि समाज में बढ़ती नफरत और मार-काट रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? हमारा संविधान हमें धर्म, मत, सम्प्रदाय, रहन-सहन, अभिव्यक्ति, आदि की जोस्वतंत्रताएँ देता है, उसकी रक्षा के लिए उनकी सरकार ने क्या किया? रोजगार बढ़ाने के लिए क्या काम हुआ? दलितों, किसानों, ग्रामीणों, आदि के कष्ट दूर करने के लिए वास्तव में क्या काम किये?

मोदी जी अपने को 'चाय वाला' बताते हुए घूम रहे थे। बेची होगी उन्होंने कभी चाय, या नहीं बेची होगी। उस समययूपी शासन से ऊबे देश को चाय बेचने वाले की नहीं, ईमानदारी और समर्पण से इस बहुतावादी देश को संविधान की मूल भावना के अनुरूप सरकार चला सकने वाले नेता की आवश्यकता थी। जनता को नरेंद्र मोदी में एक नया, ऊर्जावान, बड़े-बड़े वादों से उम्मीदें जगाने वाला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखा था। इसीलिए उन्हें जनता ने भारी बहुमत से सत्ता में पहुँचाया।

इसलिए आज हमें जवाब 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' से माँगना है, 'चाय वाला' या 'चौकीदार नरेंद्र मोदी' से नहीं।

यह वक्त है कि जनता पूछे और वे बताएँ कि पाँच साल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने वादों पर कितना अमल किया? वे बताएँ कि समाज में बढ़ती नफरत और मार-काट रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? हमारा संविधान हमें धर्म, मत, सम्प्रदाय, रहन-सहन, अभिव्यक्ति, आदि की जोस्वतंत्रताएँ देता है, उसकी रक्षा के लिए उनकी सरकार ने क्या किया? रोजगार बढ़ाने के लिए क्या काम हुआ? दलितों, किसानों, ग्रामीणों, आदि के कष्ट दूर करने के लिए वास्तव में क्या काम किये?

लेकिन नहीं, वे अपने को 'सबसे अच्छा चौकीदार' साबित करने में लगे हैं ताकि जनता ऐसे प्रश्न न पूछे जिनका जवाब उन्हें मुश्किल में डाल दे। ये जरूरी

मुद्दे और सवाल दब जाएँ। जनता 'चौकीदार' के जुमले में उलझ जाए।

विमर्श बदल देने, मुद्दों से ध्यान भटका देने, जवाबदेही टालने में हमारे नेताओं का जवाब नहीं। मोदी जी की टीम तो इस खेल की चैम्पियन साबित हो रही।

और, मान लें कि मोदी जी पिछले पाँच साल सिर्फ चौकीदारी ही करते रहे तो सवाल उठाना आवश्यक है कि फिर देश में 'चोरियों' क्यों हुईं? 'चोर' पकड़े जाने की बजाय भाग क्यों गये? और जिन 'चोरों' की सूची रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने आपको दी थी, उनके खिलाफ आपने क्या किया?

इससे बड़ा सवाल यह, यूपीए शासन की जिन 'चोरियों' का हला मचा कर आप हीरो बने, उन मामलों में 'चोरों' को अब पकड़ा क्यों नहीं?

**चूँकि मोदी जी खुद को 'चौकीदार' कह रहे हैं इसलिए ये स्वाभाविक सवाल बनते हैं: वैसे, जनता को उनसे 'प्रधानमंत्री' के रूप में और बहुत सारे सवाल पूछने हैं।**

यह चुनाव का समय है। जनता को अपने आँख-कान खुले रखने चाहिए। 'चौकीदार' की बहस में मत उलझिए। देश और समाज के सामने उपस्थित बड़े-बड़े मुद्दे उठाइए।

ध्यान दीजिए कि आपको 'चौकीदार' नहीं चुनना, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार चुननी है।

## भगत सिंह और क्रांति यानी इंकलाब



भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति यानी इंकलाब के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। अनेक लोगों ने विभिन्न तरह से क्रांति शब्द का प्रयोग किया है, मगर भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने विभिन्न दस्तावेजों में क्रांति को वैज्ञानिकता प्रदान करने की कोशिश की है। उनके लिए इंकलाब जिंदाबाद क्या था, क्रांति यानी इंकलाब के क्या मायने थे क्रांति से उनकी क्या मुराद थी? आइए उन्हीं के शब्दों में जाने की क्रांति से उनका क्या मकसद था।

18 दिसंबर 1928 को लाहौर में "हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना" के नाम से बाँटे गए पर्चे में क्रांति के बारे में कहा गया है, "हमारा उद्देश्य एक ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी।"

22 दिसंबर 1929 को मॉडर्न रिव्यू के संपादक के नाम अपने पत्र में शहीदे आजम भगत सिंह लिखते हैं "इंकलाब जिंदाबाद" के नारे को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है। इस नारे की रचना हम लोगों ने नहीं की है। यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक अपटन सिनक्लेयर ने अपने उपन्यासों "बोस्टन" और "आइल" में यही नारा अपने क्रांतिकारी पात्रों के मुख से प्रयोग कराया है।"

8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में फेंके गए पर्चे में लिखा गया है, "क्रांति द्वारा सबको समानता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ रक्तपात जरूरी है।"

6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनाई मिडिल्टन की अदालत में दिए गए ऐतिहासिक बयान में क्रांति के बारे में भगत सिंह ने बयान दिया था, "क्रांति के लिए खूनी लड़ाईयाँ अनिवार्य नहीं हैं, वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है, क्रांति से हमारा अभिप्राय है, अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन।"

"देश को एक ऐसे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका कर्तव्य है कि साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का पुनर्निर्माण करें, क्रांति से हमारा मतलब एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना से है जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वमान्य होगा।"

भूख हड़ताल के दौरान सुखदेव को लिखे पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, "क्रांति तो केवल सतत कार्य करने से, प्यलों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी और "क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही तेज होती है।"

19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ को जेल से भेजे अपने एक पत्र में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त नौजवानों का आह्वान करते हैं, "नौजवानों को क्रांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री, कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्ती और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वालों करोड़ों लोगों में क्रांति की अलख जगानी है जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा।"

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणापत्र में भगवती चरण वोहरा क्रांति के बारे में लिखते हैं, "क्रांति एक ऐसा करिश्मा है जिसे प्रकृति स्नेह करती है और जिसके बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, क्रांति ईश्वर विरोधी तो हो सकती है लेकिन मनुष्य विरोधी नहीं।"

"क्रांति एक नियम है क्रांति एक आदेश है, और क्रांति एक सत्य है।" क्रांति के बिना सुव्यवस्था, कानूनपरस्ती और प्यार स्थापित नहीं किया जा सकता।"

26 जनवरी 1930 को बम का दर्शन में भगत सिंह लिखते हैं क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद और कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उससे नए राष्ट्र और नये समाज का जन्म होगा। क्रांति से सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वह मजदूरों तथा किसानों का राज्य कायम कर उन सब अर्वाचित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश को राजनीतिक शक्ति को हथियाये बैठे हैं और अंत में क्रांति से ही देश को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।"

ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते हैं, "हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्रांति का मतलब मात्र उथल-पुथल या खूनी संघर्ष नहीं है जब हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालत को अर्थात् सरकार को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित है।"

2 फरवरी 1931 को "क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा", में क्रांति के विषय में भगत सिंह की विलक्षणता देखिए, "इंकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इसके लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। वास्तव में राज्य यानी सरकारी मशीनरी, शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का यंत्र ही है। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा आदर्श है, नए ढंग की सामाजिक रचना यानी मार्क्सवादी ढंग से समाज की रचना।"

"हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं इसके लिए बुनियादी जरूरत राजनीतिक क्रांति की है। राजनीतिक क्रांति का अर्थ यानी ताकत का अंग्रेजी हाथों से भारतीय तो हाथों में आना है और वह भी उन भारतीयों के हाथों में जिनका अंतिम लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मिलता हो।" "क्रांति उनके हित में है और उनकी अपनी है सर्वहारा, श्रमिक वर्ग की क्रांति, सर्वहारा के लिए।"

"क्रांति करना बहुत कठिन काम है, यह एक आदमी की ताकत के बस की बात नहीं है और ना ही किसी निश्चित तारीख को आ सकती है। यह तो विशेष सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है और जनता को उसके लिए तैयार करना होता है।"

"पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए अध्ययन केंद्र खोलने चाहिए, पंपलेट, पुस्तकें, मैगजीन छपने चाहिए। कक्षा में भाषण होने चाहिए। किसानों और मजदूरों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार जरूरी है पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो। चेतना ही नहीं, वर्ग-चेतना भी पैदा करनी होगी। समाजवादी सिद्धांतों के बारे में जनता को सचेत बनाने के लिए सादा और स्पष्ट लेखन बेहद जरूरी है।"

"क्रांति के लिए जरूरत है निरंतर संघर्ष करने, कष्ट सहने और कुर्बानी भरा जीवन जीने की। व्यक्तिवाद खत्म करो, व्यक्तिगत सुख के सपने उतार कर रख दो। इंच इंच कर आगे बढ़ो। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और मजबूत इरादे की जरूरत है। कष्ट और कठिनाइयों में आपकी हिम्मत न कांपे। कोई भी पराजय, धोखा, आपका दिल नहीं तोड़ सके। कष्टों के सामने आपका क्रांतिकारी जोश ठंडा न पड़े, कष्ट सहने और कुर्बानी करने के सिद्धांत से आप सफलता हासिल करेंगे।"

क्रांति यानी इंकलाब के साथ साथ आजादी के बारे में भगत सिंह कहते हैं कि वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है जिसमें लोग आपस में घुल-मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जायेंगे।

इंकलाब जिंदाबाद!  
- मुनेश त्यागी

## ज्यां ट्रेज, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, ने कहा कि सरकार को ज़मीन चाहिये तो .....

अमर्त्य सेन ने अपनी अधिकांश पुस्तकें ज्यां ट्रेज के साथ मिलकर लिखी हैं,

ज्यां ट्रेज को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिये बुलाया गया था, ज्यां ट्रेज ने नज़दीक की झुग्गी झोंपड़ी में रहना चुना,

वे रोज़ सुबह साइकिल के कैरियर पर अपना तैलिया कपड़े और साबुन लेकर यूनिवर्सिटी जाते थे,

वहाँ के बाथरूम में नहाकर ज्यां अपनी क्लास लेते थे,

ज्यां और बेला भाटिया की शादी हुई, बेला भाटिया आजकल छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकारों के लिये काम कर रही हैं,

ज्यां ट्रेज जिस झुग्गी बस्ती में रहते थे, एक बार सरकार ने उसे तोड़ने की तैयारी करी, बस्ती के लोग ज्यां ट्रेज के पास आये,

ज्यां ट्रेज ने गूगल नक्शा निकाला, उसमें कुछ देखा, और एक चिट्ठी बनाई, साथ में नक्शा नथी कर दिया और सरकार को भेज दिया,

चिट्ठी में ज्यां ने लिखा कि गूगल मैप बताता है कि दिल्ली में 12 प्रतिशत ज़मीन पर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं,

लेकिन नक्शा बताता है कि दिल्ली की 44 प्रतिशत ज़मीन पर कारों का कब्ज़ा है,

इन कारों के मालिक गलियों और सड़कों पर अपनी गाड़ियों को अवैध रूप से खड़ा करते हैं,

कारों के मालिक सरकार को पार्किंग का कोई पैसा नहीं देते,

इसलिये अगर सरकार को ज़मीन चाहिये तो वह गरीबों का मकान तोड़ने की बजाय अमीरों की कारों द्वारा अवैध रूप से घेरी गई ज़मीनों को वापिस लेने की योजना बनाये,

उसके बाद से आज तक वह झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी गई,

किसी भारतीय के दिमाग में गरीबों के पक्ष में इस तरह के ख्याल क्यों नहीं आते ?

ज्यां ट्रेज ने लम्बे समय तक झारखण्ड में आदिवासियों के भोजन के अधिकार के मुद्दे पर काम किया है,  
- हिमांशु कुमार